

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

izkf/dkj ls izdkf'kr

la- 639| ubZ fnYyh| 'kqØokj| flrEcj 9| 2016@Hkkæ 18| 1938
No. 639| NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938कारपोरेट काय^{११} मं^२ालय

अधिसूचना

नई ८द^५ली, ९सित^८ बर, 2016

सा.का.िन. 877(अ).—के^३ंीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) क^५ धारा 469 के साथ पढठत धारा 442 के तहत ^२द^५ शि^१य^१ का ^२योग करते शए िनिलिखत िनयम बनाती है, अथा^{११}त्:-

1. संि^१ो नाम और ^२ारंभ.—(1) इन िनयम^१ का संि^१ो नाम कंपनी (म^१य^१थता और सुलह), िनयम, 2016 है।
(2) ये िनयम राजप^२ म^१ ^२काशन क^५ तारीख को ^२वृत्त ह^१गे।
2. पढरभाषाएं.—(1) इन िनयम^१ म^१ जब तक ८क संदभ^{११} से अ^३यथा अपे^१ित न हो:
(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभ^२ेत है;
(ख) “^२ादेशिक िनदेशक” से कारपोरेट काय^{११} मं^२ालय म^१ के^३ंीय सरकार ~~द्वारा~~ ^{द्वारा} ^२ादेशिक िनदेशक के ^१प म^१ िनयु^१.. ि^१
अभ^२ेत है;
(ग) “उपाबंध” से इन िनयम^१ के साथ संल^१ उपाबंध अभ^२ेत है;
(घ) “^२प” या “ई-^२प” से उपाबंध म^१ िनधा^{११}रत ^२प अभ^२ेत है िजसका उपयोग उससे संबंधित मामले के िलए ८कया जाएगा;
(ङ) “पैनल” से म^१य^१थता और सुलह पैनल अभ^२ेत है।
- (2) उन श^१द^१ और पद^१ के इस िनयम म^१ उपयु^१ है ँकतु पढरभाषित नह^८ ८कया गया है और अधिनियम या कंपनी (पढरभाषा^१ ^१यौर^१ के िविनद^१शन) िनयम, 2014 म^१ पढरभाषित ८कए गए ह^८, ँकतु वही अथ^{११} ह^१गे जो इस अधिनियम या िनयम म^१ समनुदे^१ित ह^१।

3. म॥य॥थ या सुलहकता॥ का पैनल.—

(1) ००ादेशिक िनदेशक अपने ००े०० म॥ म॥य॥थ या सुलहकता॥ के ३५ म॥ िनयुि के िलए इ॥छुक या पा॥ िवशेषतः ० क॥ एक पैनल

तैयार करेगा और इस पैनल को कारपोरेट काय॥ मं॥लय क॥ वेबसाइट या के३०ीय सरकार ँ॥ारा अधिसूचित क॥ जाने वाली ढकसी अ३य वेबसाइट पर रखा जाएगा।

4380 GI/2016

(1)

(2) ००ादेशिक िनदेशक म॥य॥थ या सुलहकता॥ के ३५ म॥ पैनलीकृत होने के िहतब॥ और िनयम 4 म॥ िनंद-अपेि०त अह॥ताएं रखने

वाले ॥ि॥य॥ से आवेदन प॥ आमि॥त कर सकता है।

(3) कोई भी ि॥ जो म॥य॥थ या सुलहकता॥ के ३५ म॥ पैनल म॥ शािमल होना चाहता है और अपेि०त अह॥ताएं रखता है ००३५

एमडीसी-1 म॥ ००ादेशिक िनदेशक को आवेदन करेगा।

(4) य॥द उप िनयम (3) के अधीन ००ा॥ कोई आवेदन ००ादेशिक िनदेशक ँ॥ारा अंवीकृत कर ढदया जाता है तो

००ादेशिक िनदेशक ऐसा

करने के कारण िलिखत म॥ अभिलिखत करेगा।

(5) ००ादेशिक िनदेशक ००येक वष॥ फरवरी माह के दौरान म॥य॥थ या सुलहकता॥ के ३५ म॥ पैनलीकृत होने के िहतब॥ ि॥ से आवेदन

आमि॥त करेगा और इस पैनल को अंतन करेगा जो ००ित वष॥ 01 अ००ैल को ००वृ॥ होगी।

परंतु िव॥ वष॥ 2016-17 के िलए ००ादेशिक िनदेशक, इन िनयम॥ के ००काशन क॥ तारीख से 60 ढदन के भीतर,

म॥य॥थता और

सुलहकता॥ के पैनल म॥ शािमल करने के िलए िहतब॥ ि॥ से आवेदन आमि॥त कर सकेगा और उसके 30 ढदन॥ के भीतर

वत॥मान िव॥ वष॥ के िलए पैनल तैयार करेगा।

4. पैनलीकृत के िलए अह॥ताएं.—कोई भी ि॥ म॥य॥थ या सुलहकता॥ के ३५ म॥ िनयुि के िलए तभी अह॥ता ००ा॥

माना जाएगा जब॥क

वह:

(क) भारत के उ॥तम ३यायालय का ३यायाधीश रहा हो; या

- (ख) ढकसी उ ३यायालय के ३यायाधीश रहा हो; या
- (ग) िजला और सेशन ३यायाधीश रहा हो; या
- (घ) त०समय लागू ढकसी िविध के तहत रक्षीय ंतर पर गढठत ढकसी अधिकरण का सद॑य या रिज॑र रहा हो; या
- (ङ) भारतीय कारपोरेट िविधक सेवा या भारतीय िविधक सेवा मः पं॑ह वष॑का का अनुभव रखने वाला अधिकारी; या
- (च) कम-से-कम दस वष॑का के अनुभव के साथ एक अ॒हत िविध ॒ वसायी है; या
- (छ) चाट॑काड॑का अकाउंट॑ट या लागत लेखाकार या कंपनी सिचव के २प मः ३यूनतम पं॑ह वष॑ कः लगातार ॒वसाय कर चुका ॒
- ावसायिक रहा हो; या
- (ज) ढकसी रा३य उपभो॑का फोरम का सद॑य या अ॒य॑ रहा हो; या
- (झ) म॒य॑थ या सुलह मः िवशेष॑ िजसने म॒य॑थता या सुलह मः सफलतापूर्वक ॒रि॑श॑ण ॒र॑ ठकया हो।

5. पैनलीकृत के िलए िनरह॑ताएं.—कोई ि ३ म॒य॑थ या सुलहकता॑ के २प मः पैनल मः शा॑मल होने के िनर॒हत माना जाएगा यःद वह:

- (क) उ३मोचित ढदवा॑लिया हो या उसने ढदवा॑लिया के २प मः अधिन॑ण॒य के िलए आवेदन ठकया है तथा उसका आवेदन लं॑बित है;
- (ख) ऐसे अपराध के िलए िस॑दोष ठहराया गया हो जो के३॑ीय सरकार के िवचार मः नैतिक अधमता अंतः॒कृत से संबं॑धित है;
- (ग) सरकार या कारपोरेट के ठवा॑म॒वाधीन या िनयं॑णाधीन सेवा से हटा ढदया गया है या प॒युत ठकया गया है या िनयं॑ण
- वाले िनगम कः सेवा से हटाया गया हो;
- (घ) ढकसी समुचित अनुशासिनक ॒रि॑धिकारी ऒ॒र॑ा ढकसी अनुशासना॒मक कार॑कावाई मः दंडित ठकया गया हो; या
- (ङ) के३॑ीय सरकार कः राय मः िववाद कः िवषय-व॑ंतु या ढकसी प॑कार के संबंध मः कोई िव॒हीय या अ३य िहत रखता हो

जिसका म॒य॑थ या सुलहकता॑ के अपने क॒य ३ के िनव॑हन पर ॒रि॑तकूल ॒भाव डालने कः संभावना है।

6. म॒य॑थकता॑ या सुलहकता॑ कः िनयु॑ि के िलए आवेदन और उसकः िनयु॑ि.-

- (1) (क) संबं॑धित प॑कार उनके बीच म॒य॑थता या सुलह के िलए एकल म॒य॑थकता॑ या सुलहकता॑ के नाम पर सहमत हो सकते ह.;

(ख) यद्द दो या उससे अधिक पट्टकार ह और वे एकल मययंथकताया सुलहकताया से सहमत नह हो पा रहे ह., तो

कथंीय सरकार या

अधिकरण या अपीलीय अधिकरण ेयेक पट्ट को मययंथकताया सुलहकताया नामित करने के िलए कह सकती है या

कथंीय सरकार

या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण दोन पट्टकार के बीच मययंथता या सुलह के िलए ढकसी मययंथकताया या

सुलहकताया, जैसा भी

उचित समझे, िनयु कर सकती है।

(2) कथंीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, जैसा भी मामला हो, को उनके समट्ट लंबित ढकसी काययावाही से

संबंधित मामल

को मययंथता या सुलह के िलए भेजने का आवेदन ेप एमडीसी-2 मथ ढकया जाएगा और साथ ही एक हजार ०पए का शुक भी

संल

ढकया जाएगा।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

(3) उपिनयम (2) के तहत आवेदन क ेाट्ट पर, कथंीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, पैनल से एक या उससे

अधिक िवशेष िनयु करथगे।

(4) कथंीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, जैसा भी मामला हो, िजसके समट्ट कोई काययावाही लंबित है,

ंवेरणा से, ऐसी काययावाही से संबंधित ढकसी मामले को, यद्द पट्ट के िहत मथ उचित समझे, मययंथता या सुलह पैनल के िवशेष को भेज सकते ह।

7. पैनल से हटाया जाना.—ेादेशिक िनदेशक ढकसी ुबाद पैनल से हटा सकता है।

ि को िलिखत मथ कारण अभिलखत करके और उसे सुनवाई का अवसर देने के

8. पैनल से नाम वापस लेना.—यद्द कोई ि मययंथ या सुलहकताया पैनल से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वह ऐसा करने

के कारण दशायाते थए ेादेशिक िनदेशक को आवेदन कर सकता है तथा ेादेशिक िनदेशक ऐसा आवेदन ेाट्ट होने के पंह ढदन के अंदर उस आवेदन पर िनणयाय लेगा और तदनुसार पैनल को अंतन करेगा।

9. कितपय तय के ेकटीकरण मथ मययंथ या सुलहकताया का कत

.—(1) यह

ढकसी मययंथ या सुलहकताया का कतया

होगा ढक वह यथांथित केथंीय सरकार का अधिकरण या

अपील अधिकरण, के समट्ट उन पहरिंथित को ेकट करे िजसके कारण उसके काय के िनवयाहन मथ सतकता या

िनुपट्टता पर समुचित संदेह उठ होने क संभावना हो।

(2) ेयेक मययंथ या सुलहकताया अवलंब, अपनी िनयु के समय से और मययंथता या सुलह संबंधी काययावाहिय के

जारी रहने के दौरान पट्टकार को उपिनयम (1) मथ िलिखत पहरिंथित क मौजूदगी का ेकटीकरण करेगा।

10. िनयुि का ोयाहरण.—ठकसी कायफ्वाही मः िनयम 9 के अधीन मयथ या सुलहकताफ्वा मारा ोतुत ोकीकरण ोर्ा होने पर या ठकसी पौकार या अय ि से ोर्ा ठकसी अय सूचना के आधार पर, यद यथािथित कःीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, जहां कायफ्वाही लंबित है, समाधान है ठक ऐसी सूचना ऐसे मयथ या सुलहकताफ्वा कः वतुता या िनृपता के संबंध मः यथोचित संदेह उंप् करती है, तो वह िनयुि ोयाहरण ले सकते ह. तथा उस कायफ्वाही उनके थान पर ठकसी अय मयथ या सुलहकताफ्वा कः िनयुि कर सकते ह.;

परंतु मयथ या सुलहकताफ्वा वयं कायफ्वाहिय मः भाग न लेने कः ोयाहरत कर सकता है तथा केःीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण से अय मयथ या सुलहकताफ्वा िनयुि करने का अनुरोध कर सकता है।

11. मामल के िनपटान कःडया. —(1) मयथ या सुलह के ोयोजन के िलए मयथ या सुलहकताफ्वा िनिलिखत

डया का अनुसरण

करेगा, अथात् :

- (i) वह पौकार से परामश करके ोयेक मयथ या सुलह सः कः तारीख और समय िनधाफ्वा करेगा, जहां सभी पौकार को उपिथत होना है;
- (ii) वह यथािथित केःीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, मारा िनधाफ्वा करत ठकसी थान पर या ऐसे अय थान पर जहां पौकार और मयथ या सुलहकताफ्वा संयु ाप से समित ह मयथता या सुलह अधिवेशन का आयोजन करेगा;
- (iii) वह पौकार के साथ संयु ाप से या अलग-अलग अधिवेशन पर कर सकता है;
- (iv) ोयेक पौकार सः से दस ठदन पहले मयथ या सुलहकताफ्वा को एक संिोर्ापन सपेगा िजसमः उठाए जाने वाले मुे, िजनका सुलह करना अपेिंत है, बताते ाए और इन मु के संबंध मः उसकः िथित तथा िवषय को समझने के िलए मयथ या सुलहकताफ्वा के िलए अपेिंत सभी सूचना उपलब्ध कराएगा तथा ऐसे ापन कः एक ितिलिप िवरोधी पौकार

या पौकार को भी दी जाएगी;

परंतु, उपयु या समुचित मामल मः मयथ या सुलहकताफ्वा के िववेक से उपयु अविध को कम ठकया जा सकता है;

(v) एक पक्षकार मध्यस्थ या सुलहकर्ता को ऐसी अग्र सूचना भी उपलब्ध कराएगा जो मुद्दे के समाधान के लिए उसे अपेक्षित हो।

(2) जहां एक ही मामले में एक से अधिक मध्यस्थ या सुलहकर्ता हों तो वहां मध्यस्थ या सुलहकर्ता पहले उस पक्षकार के साथ सहमत होंगे जिसने उसने नामित करने के लिए सहमत दी है और उसके पक्ष में विवाद का निपटारा करने के लिए अग्र मध्यस्थ या सुलहकर्ता के साथ बातचीत करेंगे।

12. भारतीय सांख्यिक अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कड सीमा में न आने वाले मध्यस्थ या सुलहकर्ता—
मध्यस्थ या सुलहकर्ता मामले का निपटारा करने में भारतीय सांख्यिक अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा बाध्य नहीं होगा किंतु, वह पक्षकार के अधिकार तथा दायित्व, अपार के प्रचलन, यदि कोई हो, तथा विवाद (विवाद) कड परिस्थितियों का प्रमाण में रखते हैं, निर्णय तथा नैसर्गिक उपाय के सिद्धांत से मांग प्रदर्शित होगा।

13. पक्षकार का प्रतिनिधित्व—सभी पक्षकार साधारणतः मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा अधिसूचित सूच या अधिवेशन में
मध्यस्थ
संलग्न से या प्राधिकृत अटॉर्नी के माध्यम से उपस्थित होंगे:

परंतु, ऐसे सूच या अधिवेशन में मध्यस्थ या सुलहकर्ता कड अनुष्ठा से एक ही प्राधिकृत व्यक्ति या अधिवक्ता द्वारा उन पक्षकार का प्रतिनिधित्व ठकया जा सकता है और यथास्थित मध्यस्थ या सुलहकर्ता या केन्द्रीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण को, एक ही पक्षकार को संलग्न से उपस्थित होने का निर्देश देने या उसकड उपस्थित सुनिश्चित करने का अधिकार होगा:

परंतु यह और ठक, जो पक्षकार भारत में नहीं रहते हैं, वे मध्यस्थ या सुलहकर्ता कड अनुमित से सूच या अधिवेशन में अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

14. सत्यक तारीख पर सूच या अधिवेशन में पक्षकार कड अनुपस्थित के परिणाम—यदि कोई पक्षकार, मध्यस्थ या सुलहकर्ता द्वारा अधिसूचित सूच या अधिवेशन में लगातार दो अवसर पर सोच समझकर या जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तो मध्यस्थ या सुलहकर्ता को विफल समझा माना जाएगा और यथास्थित केन्द्रीय सरकार, अधिकरण या अपीलीय अधिकरण को, मामले कड रिपोर्ट देगा।

15. प्रशासनिक सहायता.- मध्यस्थ या सुलह संबंधी कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए मध्यस्थ या सुलहकर्ता, पक्षकार कड समित से उपयुक्त संस्थान या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता का प्रबंध कर सकते हैं।

16. पट्टिकारकद्वारा सुलह कडुंथापना.—(1) कायकवाही मः कोई पट्टिकार कारकवाई के ढकसी भी ंतर पर मय्यंथ या

सुलहकताक को नोडस

देकर अडय पट्टिकार को “बिना ढकसी पूवाकडह” सुलह का डुंथापना कर सकता है।

(2) आवेदन से संबंढित कोई पट्टिकार “पूवाकडह के साथ”, मय्यंथ या सुलहकताक को नोडस देते शए, कायकवाहियक के

ढकसी भी चरण पर

ढकसी अडय पट्टिकार को समझौते कडुंथापना दे सकता है।

17. मय्यंथ या सुलहकताक कडुंथमका.—मय्यंथ या सुलहकताक, पट्टिकारकद्वारा िववाद के ंवैकुक सुलह के िलए

डुंथकरेगा तथा डुंथेक

पट्टिकार के दिकोण को अडय पट्टिकार तक संसूचित करेगा, मुक कड पहचान कर गलतफहमयां कम करने, डुंथमकताक

को ंप करने, समझौते के डुंथ का पता लगाने तथा िववाद के िनपटान करने के िलए िवकडुंथ डुंथ करने मः उनकड

सहायता करेगा इसमः इस बात पर बल देते शए ढक उडहः डुंथभारित करने वाला िनणकय लेना पट्टिकारक कड िजमेवारी है

और वह पट्टिकारक पर िनपटारे के िनबंधित अधरोपित नहः

करेगा:

परंतु यडद दोनक पट्टिकार संमित ह. तो मय्यंथ या सुलहकताक िववाद के शीड िनपटान के िलए पट्टिकारक पर ऐसे िनयम और शत, जैसा उसे ठीक होता हो, लागू कर सकता है।

18. िनणकय लेने के िलए पट्टिकार अकेले उडरदायी ह.—पट्टिकारक को यह बात समझाई जाएगी ढक मय्यंथ या सुलहकताक

िववाद को िनपटाने के िलए ढकसी िनणकय पर पशंचने मः सहायता करता है तथा वह कोई पडरिन्धाकरण लागू नहः करेगा

या थोप नहः सकता और न ही मय्यंथ या सुलहकताक कोई आसन दे सकता है ढक मय्यंथता या सुलह से कोई पडरिन्धाकरण

होगा और मय्यंथ या सुलहकताक, पट्टिकारक पर कोई िनणकय नहः थोपेगा।

19. मय्यंथता या सुलह पूरा करने कड समय-सीमा.—(1) इन िनयमक के अधीन मय्यंथता या सुलह कड डुंथडया, मय्यंथता या

सुलह पैनल से िवशेषक या िवशेषक कड िनयुिक कड तारीख से तीन महीनक कड अविध के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(2) पैनल से िवशेषक कड िनयुिक कड तारीख से तीन महीने कड अविध समू होने पर मय्यंथता या सुलह कड डुंथकया समू हो जाएगी।

(3) अधिकरण या अपील अधिकरण के समू ढकसी भी डुंथडया के संबंध मः यडद मय्यंथता या सुलहकताक तीन माह के भीतर

समू नहः कड जा सकड हो तो अधिकरण या यथांथित अपील अधिकरण, मय्यंथ या सुलहकताक या कायककारी के ढकसी

पट्टिकार के आवेदन पर मय्यंथता या सुलहकताक के िलए अविध ऐसी अविध के िलए बड़ा सकते ह. जो तीन माह से अधिक न हो।

20. पट्टिकारकद्वारा सदभाव से कायक करना.- सभी पट्टिकार िववाद को यथासमय िनपटान के िलए कायकवाहियक मः

सदभाव से भाग लेने के िलए वचनबक हकगे।

21. सूचना कऽ गोपनीयता, ँकटीकरण तथा अँवीकायऽता.—(1) जब मऱयँथ या सुलहकताऽता ढकसी पँकार से िवाद के िवषय मऽ तःयांमक सूचना ँाँ करता है तो वह दूसरे पँकार को ऐसी सूचना के सार का ँकटीकरण करऽगे ताऽक अऽय पँकार को ऐसे ँपीकरण

ँतुत करने का मौका िमल सके जो वह िवचार समझे:

परंतु जब कोई पँकार इस िविशऽतऽता पर मऱयँथ या सुलहकताऽता को सूचना देता है ढक इसे गोपनीय रखा जाए, तब मऱयँथ या सुलहकताऽता अऽय पँकार को सूचना का ँकटीकरण नहऽ करेगा।

(2) मऱयँथ या सुलहकताऽता िवँतार को उस ँमता मऽ कायऽता करते ऽए अभिलेखी, ढरपोटऽ या अऽय दँतावेजऽ को ँाँ या िात या तैयारी

गोपनीय रखी जाएगी तथा मऱयँथ या सुलहकताऽता को, दँतावेज संबंधी सूचना और मऱयँथ या सुलह के दौरान ऽए घटनाऽम को यथाँिथित कऽँीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण या अऽय ँाँधिकरण या अऽय ँिऽ या ँिऽ-समूहऽ के समँ ँकट करने के िलए बाँय नहऽ ढकया जाएगा।

(3) पँकार, मऱयँथता या सुलह के दौरान घऽटत घटनाऽम के संबंध मऽ गोपनीयता बनाए रखऽगे तथा अऽय कायऽतावाँहयऽ मऽ ऐसी सूचना पर िनभऽता नहऽ रहऽगे या उसे ँँतुत नहऽ करऽगे जैसे ढक:

(i) मऱयँथता या सुलह संबंधी कायऽतावाँहयऽ के दौरान पँकार ँऽऽारा अभिऽ ँ दँिऽकोण;

¹Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

(ii) मऱयँथता या सुलह के दौरान ँाँ ढकए गए दँतावेज, जो गोपनीय रखे जाने के िलए अपेँित थे, या पँकार, मऱयँथ या

सुलहकताऽता ँऽऽारा ढदए गए अऽय ढटऽपणी, ँाँप या सूचना;

(iii) मऱयँथ या सुलहकताऽता ँऽऽारा ढदए गए ँँथापना या अभिऽ ँ दँिऽकोण;

(iv) मऱयँथता या सुलह संबंधी कायऽतावाँहयऽ के दौरान ढकसी पँकार ँऽऽारा दी गई ँवीकृति;

(4) मऱयँथता या सुलह कऽ कोई दँय-ऽऽ ढरकँडग नहऽ कऽ जाएगी।

(5) मऱयँथ या सुलहकताऽता ँऽऽारा पँकारऽ के बयान या साँँयऽ कऽ अभिलखत नहऽ कऽ जाएगी।

22. एकांतता.—मऱयँथता या सुलह सँ या अधिवेशनऽ का आयोजन एकांतता मऽ ढकया जाएगा, जहाँ िनयम 13 मऽ उँलिखत ँिऽ पँकारऽ का ँतिनिधँव करने के हकदार हँगे तथापि अऽय ँिऽ

सदँय पँकारऽ कऽ अनुमित तथा मऱयँथ या सुलहकताऽता कऽ सहमित से ही उपिँथत हो सकते हँ।

23. सदभावपूर्वक कऽ गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—कसी भी मध्य या सुलहकता का को सिसवल या दांडक कार्रवाई के लिए मध्य या सुलह संबंधी कायदावाहिय के दौरान सदभाव से एकए गए कायदा या चूक के लिए जिम्मेदार नहल ठहराया जाएगा और न ही मध्य या सुलह संबंधी कायदावाहिय के दौरान उसके द्वारा सूचना या उसके द्वारा कऽ गई कार्रवाई कऽ जांच करने या उसके द्वारा तैयार व उत्तुत ाप या अभिलेख के लिए उसे कसी वाद या कायदावाही के लिए कसी प्रकार द्वारा, कर्तीय सरकार यथास्थित अधिकरण या अपील अधिकरण, के समी उत्तुत होने का समन ढदया जाएगा।

24. मध्य या सुलहकता और कर्तीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण के मध्य संसूचना.—कर्तीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, मध्य प्रकार का िर्वास तथा मध्य या सुलहकता कऽ तटथता बनाए रखने के लिए

मध्य या सुलहकता तथा कर्तीय

सरकार यथास्थित या अधिकरण या अपील अधिकरण, के मध्य िवषय वतु के संबंध मध्य कोई संवाद नहल होगा:

परंतु यद मध्य या सुलहकता और यथास्थित कर्तीय सरकार या अधिकरण या अपील अधिकरण, के मध्य कोई संसूचना अपेित हो तो यह संवाद िलिखत ाप मध्य ढकया जाएगा तथा इसकऽ ितियां प्रकार या िधिकृत ितिनिधय को दी जाएगी:

परंतु यह और ढक मध्य या सुलहकता तथा कर्तीय सरकार या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण, के मध्य संसूचना, मध्य या सुलहकता द्वारा िलिखत के बारे मध्य संवाद करने के लिए सीमित ढकया जाएगा:

(i) प्रकार कऽ अनुपिथित के बारे मध्य;

(ii) प्रकार कऽ समित के बारे मध्य;

(iii) उसके िनधाकरण के संबंध मध्य ढक यह मामला मध्यता या सुलह द्वारा पहरिनधाकरण के उपयु नहल है;

(iv) प्रकार के मध्य िवाद के िनपटान के बारे मध्य।

25. पहरिनधाकरण करार.—(1) जहां कायदावाही मध्य सभी मु या कुछ मु के संबंध मध्य प्रकार के मध्य मध्य कोई सहमित होती है वहां इसे िलिखत ाप ढदया जाएगा तथा प्रकार द्वारा इसे हंताित ढकया जाएगा और यद कसी काउंसिल ने प्रकार का ितिनिधव ढकया है तब मध्य या सुलहकता पहरिनधाकरण करार पर उनके भी हंताित करेगा।

(2) पॉकार एनारा इस ेकार हंताँरत पहरिनाधारण करार मयँथ या सुलहकताका के पास दाखिल ढकया जाएगा जो करार को उसके एनारा हंताँरत अएषण पु के साथ िलफाफे मः यथाँथित कःँीय सरकार या अधकरण या अपीलीय अधकरण, को अएषित करेगा।

(3) जहां िनयम 19 मः दी गई समय सीमा से पहले पॉकार के मयँथ कोई पहरिनाधारण नहल होता है या जहां मयँथ या सुलहकताका का मानना हो ढक कोई करार संभव नहल है वहां वह इसक जानकारी िलिखत ढप मः यथाँथित कःँीय सरकार या अधकरण, अपील अधकरण को देगा।

26. पहरिनाधारण को अभलेखित करने तथा आदेश पाहरत करने के िलए तारीख िनयत करना.—(1) यथाँथित कःँीय सरकार या

अधकरण या अपील अधकरण, िनयम 25 के तहत मयँथ या सुलहकताका से हरपोटका ेा होने के सामाअतः चौदह ढदन के भीतर सुनवाई कः तारीख िनयत करेगा और सुनवाई कः ऐसी तारीख पर, यढद यथाँथित कःँीय सरकार या अधकरण या अपील अधकरण, समाधान हो ढक पॉकार ने अपने िववाद का िनपटारा कर िलया है तो वह उसके िनयम के अनुसार एक आदेश पाहरत करेगा।

(2) यढद वाद या कायकावाहिय मः उठे कितपय मु पर ही पहरिनाधारण होता है तब यथाँथित कःँीय सरकार या अधकरण या अपील अधकरण उपनयम (1) मः िलिखत अनुसार, िजसके आधार पर कोई आदेश पाहरत ढकया गया है, शेष मु पर िनणकाय लेने के िलए कायकावाही करःगे।

27. मयँथता और सुलह का य.—(1) िववाद को मयँथ या सुलहकताका के पास भेजते समय, यथाँथित कःँीय सरकार या अधकरण या अपीलीय अधकरण, मयँथ या सुलहकताका फःस िनयत कर सकती है और जहां तक संभव हो, ेयेक सः या अधवेशन के िलए पाहरमिक देने कः बजाए एक समेढकत रािश तय कः जाएगी।

(2) मयँथ या सुलहकताका के फःस समेत मयँथ या सुलह के य, ेशासिनक सहयोग कः लागत, तथा संबँधित अअय आनुषंगिक य,

िविभू ेयितयोगी पॉकार एनारा समान ढप से या जैसा ढक केःँीय सरकार या अधकरण या अपील अधकरण एनारा िनदेशित ढकया जाए, वहन ढकया जाएगा।

(3) ेयेक पॉकार िवशेषी सहित अपनी ओर से साँँय या दँतावेज को पेश करने कः लागत वहन करेगा।

(4) मयँथ या सुलहकताका, मयँथता या सुलह के आरंभ होने से पहले, मयँथ या सुलहकताका को पाहरमिक रािश या मयँथता या

सुलह कः संभावित लागत के बराबर िहँसे को जमा करने का िनदेश पॉकार को दे सकता है।

(6) म॥य०धता या सुलह केवल उपिनयम (4) म॥ उ० लिखत रा०शि को जमा करवाने पर ही ००ारंभ होगी और य०द ऐसे ००ारंभ से पहले रा०शि

उलंघन कर रहा है, तो वह ेादेशिक िनदेशक को इसक\$ सूचना तोकाल दे।

29. मयथम या ऽयायिक कायवाहय का अभगम लेना.—कोई भी पौ, इन िनयम के तहत मयथता या सुलह के दौरान,

कसी

मामले, जो क मयथता या सुलह क िवषयवतु है, के िलए कोई मयथम ऽयायिक कायवाही शु नह करेगा, िसवाय

इसके क कोई

पौकार मयथम या ऽयायिक कायवाही का आरंभ कर सकता है जहां उसके मतानुसार ऐसी कायवाही उसके अधिकार को

सरौत करने

िलए अपेौत ह।

30. मयथता या सुलह पैनल के नह भेजे जाने वाले मामले.—िंिलिखत मामले मयथता या सुलह के िलए नह भेजे जाएंगे:-

(क) इस अधिनयम के अयाय-XIV के अधीन िनरीण या अवेण संबंधी कायवाहय से संबंधित मामले; या वे मामले जो चूक

या

अपराध से संबंधित ह िजसके िलए एक या अधिक पौकार ने समझौते के िलए आवेदन कया हो।

(ख) वे मामले िजनम कपट जाली दतावेज गढ़ना, कूटरचना, ितपण, पीड़न के गंभीर और िविनंद अभकिथत

अंतविलित ह।

(ग) वे मामले िजनम दांडिक और गैर-शमनीय अपराध के िलए अभयोजन अंतविलित है।

(घ) वे मामले िजसम लोकिहत या असंय ि जो यथािंथित केर्ीय सरकार, या अधिकरण या अपील अधिकरण, के

समौ पौकार

नह ह., का िहत अंतविलित हो।

¹Hkkx llμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7

ेप एमडीसी-1

[कंपनी (मयथता और सुलह) िनयम, 2016 का िनयम 3(3) देख]

मयथ या सुलहकता को पैनल म शामिल करने का आवेदन

सेवा म,

ेादेशिक िनदेशक

.....

.....

म. _____ सुपु या सुपुी या पकी* ी _____ आवास _____

_____ (पता) अपनी सेवा को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकृत करना

चाहता

होता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थान पर स्वीकृत नियम कायम या मुद्रा पर कायम कर सकें।

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

म. पिछले _____ वर्ष से निम्नलिखित स्तरों में अपेक्षा अहमता और अनुभव रखता है, इस संबंध में मेरा संक्षेप

विवरण यहाँ

आवश्यक आपन जिसमें मेरी अहमता, अनुभव, व्यावसायिक सबूत और घोषणापत्र सहित उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं,

सहक रूप से

अनुमानित दो सेट में संलग्न है।

संक्षेप में अनुभव का स्तर

म. कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2014 और ऐसे अन्य सुसंगत नियम या आचार संहिता या दशानिदश का पालन

करेंगे जो

समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

म. यह किंतु करता है कि पैनल के स्तरों का सूचना प्राप्त होती है, आवश्यक दस्तावेज को भी निष्पादित किया जाएगा।

म. आपसे पैनल में पैनल के लिए मेरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

ॐ

थान:

हस्ताक्षर

तारीख:

अनुलोक:

(मुहर)

*जो लागू न हो, उसे हटा दें।

रूप एमडीसी-2

[कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2016 का नियम 6(2) देखें]

पैनल को मामला निर्यात का आवेदन

सेवा में,

(अभिहित अधिकारी)

केंद्रीय सरकार/अधिकरण/अपील अधिकरण

म. _____ सुपुत्र या सुपुत्री या पत्नी श्री _____ आवास

_____ (पता) अधिनियम क३ धारा _____ के अधीन
के३्रीय सरकार/अधिकरण/अपील अधिकरण के समी३ काय३वाही, संदभ३ सं३या _____ (य३द कोई
हो) म३ एक
प३कार होने के नाते इस मामले को म३य३थ और सुलह के पैनल म३ भेजने का आवेदन करता ह३।

_____ (३द३ फ३स का ३यौरा) के ३३३रा अपे३ित फ३स का संद३ कर ३दया गया है।

३

थान:

तारीख:

ह३ता३र

*जो लागू नह३ होता: उसे हटा द३।

[फा. सं.-1/36/2013-सीएल-V]

अमरदीप ३सह भा३टया, संयु३ सिचव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2016

G.S.R. 877 (E).—In exercise of the powers conferred under section 442 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. **Short Title and Commencement .**—(1) These rules may be called the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016.
2. **Definitions .**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) “Regional Director” means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director ;
 - (c) “Annexure” means the annexure attached to these rules ;
 - (d) “Form” or “e-Form” means a form set forth in the Annexure which shall be used for the matter to which it relates ;
 - (e) “Panel” means the Mediation and Conciliation Panel.
- 1Hkkx ३३[k.M 3(i)° Hkkjr dk jkti=k % v1k/kj.k 9
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules.
3. **Panel of mediators or conciliators .**—(1) Regional Director shall prepare a panel of experts willing and eligible to be appointed as mediators or conciliators in the respective regions and such panel shall be placed on the website of the Ministry of Corporate Affairs or on any other website as may be notified by the Central Government.
- (2) The Regional Director may invite applications from persons interested in getting empanelled as mediator or conciliator and possessing the requisite qualifications specified in Rule 4.

- (3) A person who intends to get empanelled as mediator or conciliator and possesses the requisite qualifications shall apply to the Regional Director in



Form MDC-1.

(4) Application received under sub-rule (3), if rejected by the Regional Director, the Regional Director shall record the reasons in writing for the same.

(5) The Regional Director shall invite applications from persons interested in getting empanelled as mediator or conciliator every year during the month of February and update the Panel which shall be effective from 1st of April of every year:

Provided that for Financial Year 2016-17, the Regional Director may call for applications from the persons interested in getting empanelled as mediator or conciliator, within 60 days from the date of publication of these rules and prepare the panel for the current financial year within a period of 30 days.

4. Qualifications for empanelment.—A person shall not be qualified for being empanelled as mediator or conciliator unless he —

- (a) has been a Judge of the Supreme Court of India ; or
- (b) has been a Judge of a High Court ; or
- (c) has been a District and Sessions Judge ; or
- (d) has been a Member or Registrar of a Tribunal constituted at the National level under any law for the time being in force ; or
- (e) has been an officer in the Indian Corporate Law Service or Indian Legal Service with fifteen years experience ; or
- (f) is a qualified legal practitioner for not less than ten years ; or
- (g) is or has been a professional for at least fifteen years of continuous practice as Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary ; or
- (h) has been a Member or President of any State Consumer Forum ; or
- (i) is an expert in mediation or conciliation who has successfully undergone training in mediation or conciliation.

5. Disqualifications for empanelment.—A person shall be disqualified for being empanelled as mediator or conciliator, if he —

- (a) is an undischarged insolvent or has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending ;
- (b) has been convicted for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude ;
- (c) has been removed or dismissed from the service of the Government or the Corporation owned or controlled by the Government ;
- (d) has been punished in any disciplinary proceeding, by the appropriate disciplinary authority ; or
- (e) has, in the opinion of the Central Government, such financial or other interest in the subject matter of dispute or is related to any of the parties, as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a mediator or conciliator.

6. Application for appointment of Mediator or Conciliator and his appointment -

- (1) (a) Parties concern may agree on the name of the sole mediator or conciliator for mediation or conciliation between them;
- (b) Where, there are two or more sets of parties and are unable to agree on a sole mediator or conciliator, the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal may ask each party to nominate the mediator or conciliator or the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal may appoint the mediator or conciliator, as may be deemed necessary for mediation or conciliation between the parties.

- (2) The application to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, for referring the matter pertaining to any proceeding pending before it for mediation or conciliation shall be in



Form MDC-2 and shall be accompanied with a fee of one thousand rupees.

(3) On receipt of an application under sub-rule (2), the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal shall appoint one or more experts from the panel.

(4) The Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, before which any proceeding is pending may, *suo motu*, refer any matter pertaining to such proceeding to such number of experts from the Mediation and Conciliation Panel, if it deems fit in the interest of parties.

7. Deletion from the Panel .— The Regional Director may by recording reasons in writing and after giving him an opportunity of being heard, remove any person from the Panel.

8. Withdrawing name from Panel.—Any person who intends to withdraw his name from the Mediation and Conciliation Panel may make an application to the Regional Director indicating the reasons for such withdrawal and the Regional Director shall take a decision on such application within fifteen days of receipt of such application and update the Panel accordingly.

9. Duty of mediator or conciliator to disclose certain facts.—(1) It shall be the duty of a mediator or conciliator to disclose to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, about any circumstances which may give rise to a reasonable doubt as to his independence or impartiality in carrying out his functions.

(2) Every mediator or conciliator shall from the time of his appointment and throughout continuance of the mediation or conciliation proceedings, without any delay, disclose to the parties about existence of any circumstance referred to in sub-rule (1).

10. Withdrawal of appointment .—The Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be, upon receiving any disclosure furnished by the mediator or conciliator under rule 9, or after receiving any other information from a party or other person in any proceeding which is pending and on being satisfied that such disclosures or information has raised a reasonable doubt as to the independence or impartiality of such mediator or conciliator, may withdraw his appointment and in his place, appoint any other mediator or conciliator in that proceeding :

Provided that the mediator or conciliator may, offer to withdraw himself from such proceeding and request the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be to appoint any other mediator or conciliator.

11. Procedure for disposal of matters .—(1) For the purposes of mediation and conciliation, the mediator or conciliator shall follow the following procedure, namely :-

(i) he shall fix, in consultation with the parties, the dates and the time of each mediation or conciliation session, where all parties have to be present ;

(ii) he shall hold the mediation or conciliation at the place decided by the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, or such other place where the parties and the mediator or conciliator jointly agree ;

(iii) he may conduct joint or separate meetings with the parties ;

(iv) each party shall, ten days before a session, provide to the mediator or conciliator a brief memorandum setting forth the issues, which need to be resolved, and his position in respect of those issues and all information reasonably required for the mediator or conciliator to understand the issue and a copy of such memorandum shall also be given to the opposite party or parties:

Provided that in suitable or appropriate cases, the above mentioned period may be reduced at the discretion of the mediator or conciliator;

(v) each party shall furnish to the mediator or conciliator such other information as may be required by him in connection with the issues to be resolved.

(2) Where there is more than one mediator or conciliator, the mediator or conciliators may first concur with the party that agreed to nominate him and thereafter interact with the other mediator or conciliator, with a view to resolve the dispute.

12. Mediator or Conciliator not bound by the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Civil Procedure, 1908 .—The mediator or conciliator shall not be bound by the Indian Evidence Act, 1872 or the Code of Civil Procedure, 1908 while disposing the matter, but shall be guided by the principles of fairness and natural justice, having regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade, if any, and the circumstances of the dispute.

¹Hkkx Hk.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

13. Representation of parties.— The parties shall ordinarily be present personally or through an authorised attorney at the sessions or meetings notified by the mediator or conciliator:

Provided that the parties may be represented by an authorised person or counsel with the permission of the mediator or conciliator in such sessions or meetings and the mediator or conciliator or the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be, shall be entitled to direct or ensure the presence of any party to appear in person:

Provided further that the party not residing in India may, with the permission of the mediator or conciliator, be represented by his or her authorised representative at the sessions or meetings.

14. Consequences of non-attendance of parties at sessions or meetings on due dates.—If a party fails to attend a session or a meeting fixed by the mediator or conciliator deliberately or wilfully for two consecutive times, the mediation or conciliation shall be deemed to have failed and mediator or conciliator shall report the matter to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be.

15. Administrative assistance.— In order to facilitate the conduct of mediation or conciliation proceedings, the mediator or conciliator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person.

16. Offer of settlement by parties.—(1) Any party to the proceeding may, “without prejudice” offer a settlement to the other party at any stage of the proceedings, with a notice to the mediator or conciliator.

(2) Any party to the proceeding may make a, “with prejudice” offer to the other party at any stage of the proceedings with a notice to the mediator or conciliator.

17. Role of Mediator or Conciliator .— The mediator or conciliator shall attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute by the parties, and communicate the view of each party to the other, assist them in identifying issues, reducing misunderstandings, clarifying priorities, exploring areas of compromise and generating options in an attempt to resolve the dispute, emphasising that it is the responsibility of the parties to take decision which affect them and he shall not impose any terms of settlement on the parties :

Provided that on consent of both the parties, the mediator or conciliator may impose such terms and conditions on the parties for early settlement of the dispute as he may deem fit.

18. Parties alone responsible for taking decision.—The parties shall be made to understand that the mediator or conciliator facilitates in arriving a decision to resolve the dispute and that he shall not and cannot impose any settlement nor the mediator or conciliator give any assurance that the mediation or conciliation shall result in a settlement and the mediator or conciliator shall not impose any decision on the parties.

19. Time limit for completion of mediation or conciliation.— (1) The process for any mediation or conciliation under these rules shall be completed within a period of three months from the date of appointment of expert or experts from the Panel.

(2) On the expiry of three months from the date of appointment of expert from the Panel, the mediation or conciliation process shall stand terminated.

(3) In case of mediation or conciliation in relation to any proceeding before Tribunal or Appellate Tribunal which could not be completed within three months, the Tribunal or as the case may be, the Appellate Tribunal, may on the application of mediator or conciliator or any of the party to the proceedings, extend the period for mediation or conciliation by such period not exceeding three months.

20. Parties to act in good faith.— All the parties shall commit to participate in the proceedings in good faith with the intention to settle the dispute.

21. Confidentiality, disclosure and inadmissibility of information .—(1) When a mediator or conciliator receives factual information concerning the dispute from any party, he shall disclose the substance of that information to the other party, so that the other party may have an opportunity to present such explanation as it may consider appropriate :

Provided that when a party gives information to the mediator or conciliator subject to a specific condition that the information may be kept confidential, the mediator or conciliator shall not disclose that information to the other party.

(2) The receipt or perusal, or preparation of records, reports or other documents by the mediator or conciliator, while serving in that capacity shall be confidential and the mediator or conciliator shall not be compelled to divulge information regarding those documents nor as to what transpired during the mediation or conciliation before the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal or as the case may be, or any other authority or any person or group of persons.

(3) The parties shall maintain confidentiality in respect of events that transpired during the mediation and conciliation and shall not rely on or introduce the said information in other proceedings as to —

- (i) views expressed by a party in the course of the mediation or conciliation proceedings ;
 - (ii) documents obtained during the mediation or conciliation which were expressly required to be treated as confidential or other notes, drafts or information given by the parties or the mediator or conciliator.
 - (iii) proposals made or views expressed by the mediator or conciliator ;
 - (iv) admission made by a party in the course of mediation or conciliation proceedings.
- (4) There shall be no audio or video recording of the mediation or conciliation proceedings.
- (5) No statement of parties or the witnesses shall be recorded by the mediator or conciliator.

22. Privacy.— The mediation or conciliation sessions or meetings shall be conducted in privacy where the persons as mentioned in rule 13 shall be entitled to represent parties but other persons may attend only with the permission of the parties and with the consent of the mediator or conciliator.

23. Protection of action taken in good faith .—No mediator or conciliator shall be held liable for anything, which is done or omitted to be done by him, in good faith during the mediation or conciliation proceedings for civil or criminal action nor shall be summoned by any party to the suit or proceeding to appear before the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, to testify regarding information received by him or action taken by him or in respect of drafts or records prepared by him or shown to him during the mediation or conciliation proceedings.

24. Communication between mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal.—In order to preserve the confidence of parties in the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be and the neutrality of the mediator or conciliator, there shall be no communication between the mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, in the subject matter :

Provided that, if any communication between the mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, is necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or the authorised representative :

Provided further that communication between the mediator or conciliator and the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, shall be limited to communication by the mediator or conciliator:

- (i) about the failure of the party to attend ;
- (ii) about the consent of the parties ;
- (iii) about his assessment that the case is not suited for settlement through the mediation or conciliation;
- (iv) about settlement of dispute between the parties.

25. Settlement agreement .— (1) Where an agreement is reached between the parties in regard to all the issues or some of the issues in the proceeding, the same shall be reduced to writing and signed by the parties and if any counsel has represented the parties, the conciliator or mediator may also obtain the signature of such counsel on the settlement agreement.

(2) The agreement of the parties so signed shall be submitted to the mediator or conciliator who shall, with a covering letter signed by him, forward the same to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be.

(3) Where no agreement is reached at between the parties, before the time limit specified in rule 19, or where the mediator or conciliator is of the view that no settlement is possible, he shall report the same to the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, in writing.

26. Fixing date for recording settlement and passing order .—(1) The Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be, shall fix a date of hearing normally within fourteen days from the date of receipt of the report of the mediator or conciliator under rule 25 and on such date of hearing, if the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, is satisfied that the parties have settled their dispute, it shall pass an order in accordance with terms thereof.

(2) If the settlement disposes of only certain issues arising in the proceeding, on the basis of which any order is passed as stated in sub-rule (1), the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, shall proceed further to decide the remaining issues.

27. Expenses of the mediation and conciliation.—(1) At the time of referring the matter to the mediation or conciliation, the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, may fix the fee of the mediator or conciliator and as far as possible, a consolidated sum may be fixed rather than for each session or meeting.

१Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

13

(2) The expense of the mediation or conciliation including the fee of the mediator or conciliator, costs of administrative assistance and other ancillary expenses concerned, shall be borne equally by the various contesting parties or as may be otherwise directed by the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be.

(3) Each party shall bear the costs for production of witnesses on his side including experts or for production of documents.

(4) The mediator or conciliator may, before the commencement of the mediation or conciliation, direct the parties to deposit equal share of the probable costs of the mediation or conciliation including the fees to be paid to the mediator or conciliator.

(5) If any party or parties do not pay the amount referred to sub-rule (4), the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal, as the case may be, shall on the application of the mediator or conciliator, or any party, issue appropriate directions to the concerned parties.

(6) The mediation or conciliation shall commence only on the deposit of amount referred to in sub-rule (4) and in case amount is not paid before such commencement, the mediation or conciliation shall be deemed to have terminated.

28. Ethics to be followed by Mediator or Conciliator.—The mediator or conciliator shall—

- (a) follow and observe the rules strictly and with due diligence ;

- (b) not carry on any activity or conduct which shall reasonably be considered as conduct unbecoming of a mediator or conciliator ;
- (c) uphold the integrity and fairness of the mediation or conciliation process;
- (d) ensure that the parties involved in the mediation or conciliation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the process ;
- (e) satisfy himself or herself that he or she is qualified to undertake and complete the assignment in a professional manner ;
- (f) disclose any interest or relationship likely to affect impartiality or which might seek an appearance of partiality or bias ;
- (g) avoid, while communicating with the parties, any impropriety or appearance of impropriety ;
- (h) be faithful to the relationship of trust and confidentiality imposed in the office of mediator or conciliator ;
- (i) conduct all proceedings related to the resolutions of a dispute, in accordance with the relevant applicable law ;
- (j) recognise that the mediation or conciliation is based on principles of self-determination by the parties and that the mediation or conciliation process relies upon the ability of parties to reach a voluntary, undisclosed agreement ; and
- (k) maintain the reasonable expectations of the parties as to confidentiality and refrain from promises or guarantees of results.

Provided that if any party finds conduct of mediator or conciliator violative of ethics laid down in this rule, the party may immediately bring it to the notice of the Regional Director.

29. Resort to arbitral or judicial proceedings .—The parties shall not initiate, during the mediation or conciliation under these rules, any arbitral or judicial proceedings in respect of a matter that is the subject-matter of the mediation or conciliation, except that a party may initiate arbitral or Judicial proceedings, where, in his, opinion, such proceedings are necessary for protecting his rights.

30. Matters not to be referred to the mediation or conciliation .—The following matters shall not be referred to mediation or conciliation, namely :—

- (a) the matters relating to proceedings in respect of inspection or investigation under Chapter XIV of the Act; or the matters which relate to defaults or offences for which applications for compounding have been made by one or more parties.
- (b) cases involving serious and specific allegations of fraud, fabrication of documents forgery, impersonation, coercion etc.
- (c) cases involving prosecution for criminal and non-compoundable offences.
- (d) cases which involve public interest or interest of numerous persons who are not parties before the Central Government or the Tribunal or the Appellate Tribunal as the case may be.

FORM MDC-1

[See rule 3(3) of the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016]

Application for Empanelment of Mediator or Conciliator on the Panel

To

The Regional Director _____

I S/o or D/o or W/o* resident of

..... (address) am hereby pleased to offer my services as
Mediator or Conciliator so as to take up any assignment or matters referred
by the Central Government at the places furnished hereunder:

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

I possess requisite qualifications and experience in the following fields for the past ____ years. In
this regard, my resume or an illustrative memoranda as to my qualifications, experience, notable
achievements with relevant proofs and declaration are enclosed hereto in two sets duly attested.

Area of Experience in brief :

I shall abide by the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016 and such other relevant rules or Code of
Conduct or Guidelines as may be specified from time to time.

I state that upon the receipt of the intimation of offer of empanelment, the necessary documentation shall also be
executed.

I request you to consider my application for empanelment in the Panel.

Place :

Dated :

Encl :

(Seal)

Signature

*Strike off whichever is not applicable.

¹Hkkx Πμ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

15

FORM MDC-2

[See rule 6(2) of the Companies (Mediation and Conciliation) Rules, 2016]

Application for referring the matter to the Panel

To

The (Designated Officer)

The Central Government/Tribunal/Appellate Tribunal.

I S/o or D/o or W/o*.....resident of

_____ (address) being a party in the proceeding before Central Government/Tribunal/Appellate Tribunal under section _____ of the Act bearing reference number _____ (if any) hereby apply for referring the matter to the Mediation and Conciliation Panel.

The requisite fee has been paid vide(details of fees paid).

Place :

Dated :

SIGNATURE

* Strike off whichever is not applicable

[F. No.1/36/2013-CL. V]

AMARDEEP S BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA Digitally signed by
HARINDRA KUMAR
KUMAR Date: 2016.09.15
11:17:36 +05'30'

